नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 172
दि. 27.03.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# चंदे की दौड़ में एकतरफा बढ़त: ₹6648 करोड़ में 91% हिस्सा लेकर सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत बाकी दल काफी पीछे

देश की राजनीति में धनबल की भूमिका कितनी निर्णायक होती जा रही है, इसका एक बेहद स्पष्ट और चौंकाने वाला चित्र वित्त वर्ष 2024-25 के चंदे के आंकड़ों से सामने आया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए विवरण के अनुसार इस अवधि में देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर 6648.563 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ, लेकिन इस पूरी राशि का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। आंकड़े बताते हैं कि कुल चंदे का 91 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भाजपा को मिला, जो भारतीय राजनीति में आर्थिक असमानता और संसाधनों के केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है।

अगर विस्तार से देखें तो भाजपा को 5522 दानदाताओं से कुल 6074.015 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ, जो कि अन्य सभी प्रमुख राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे के संयुक्त आंकड़े से भी कई गुना अधिक है। इसके मुकाबले देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2501 दानदाताओं से 517.394 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन का भी संकेत देता है, क्योंकि भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले केवल दोगुने दानदाता ही मिले, लेकिन चंदे की राशि करीब 12 गुना ज्यादा रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा को मिलने वाला दान औसतन कहीं अधिक बड़ी रकम का है।

अन्य दलों की स्थिति और भी सीमित दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी को 2554 दानदाताओं से 38.106 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 741 दानदाताओं से 16.957 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। पूर्वोत्तर की प्रमुख पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी को महज 25 दानदाताओं से 2.091 करोड़ रुपये का योगदान मिला। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर पिछले 19 वर्षों की तरह 20 हजार रुपये से अधिक के किसी भी चंदे को शून्य दर्शाया है, जो अपने आप में एक अलग और विशिष्ट रुख को दर्शाता है।

इन आंकड़ों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कुल चंदे में भारी उछाल देखने को मिला है। राष्ट्रीय दलों के कुल चंदे में करीब 4104.285 करोड़ रुपये यानी 161 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें भाजपा के चंदे में 171 प्रतिशत की वृद्धि सबसे उल्लेखनीय रही, जो 2243.947 करोड़ रुपये से बढ़कर 6074.015 करोड़ रुपये हो गया। कांग्रेस के चंदे में भी 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आम आदमी पार्टी के चंदे में 244 प्रतिशत और नेशनल पीपुल्स पार्टी के चंदे में 1313 प्रतिशत तक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई।

राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की राजधानी दिल्ली चंदा देने के मामले में सबसे आगे रही, जहां से राजनीतिक दलों को कुल 2639.48 करोड़ रुपये का योगदान मिला। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान रहा, जहां से 2438.86 करोड़ रुपये का चंदा मिला। तीसरे स्थान पर गुजरात रहा, जहां से 309.17 करोड़ रुपये का योगदान आया। ये आंकड़े इस बात को भी दर्शाते हैं कि देश के आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों और महानगरों का राजनीतिक फंडिंग में कितना बड़ा योगदान है। अगर चंदे के स्रोतों की बात करें तो कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। कुल चंदे में से 92.18 प्रतिशत हिस्सा कॉरपोरेट या व्यापारिक घरानों से आया है। 3244 कॉरपोरेट दानदाताओं ने कुल 6128.787 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि 7900 व्यक्तिगत दानदाताओं ने 505.66 करोड़ रुपये का चंदा दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि राजनीतिक फंडिंग में कॉरपोरेट सेक्टर का दबदबा लगातार बढ़ रहा है।

पार्टीवार कॉरपोरेट और व्यक्तिगत चंदे के आंकड़े भी काफी कुछ बयां करते हैं। भाजपा को 2794 कॉरपोरेट दानदाताओं से 5717.167 करोड़ रुपये और 2627 व्यक्तिगत दानदाताओं से 345.94 करोड़ रुपये मिले। यह कॉरपोरेट चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों को मिले कुल कॉरपोरेट चंदे से करीब 13 गुना अधिक है। वहीं कांग्रेस को 112 कॉरपोरेट दानदाताओं से 383.8605 करोड़ रुपये और 2357 व्यक्तिगत दानदाताओं से 132.3885 करोड़ रुपये का योगदान मिला।

यह पूरा परिदृश्य भारतीय राजनीति में आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण की ओर संकेत करता है, जहां एक ओर एक पार्टी के पास अपार वित्तीय शक्ति है, वहीं अन्य दल सीमित संसाधनों के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या यह असंतुलन भविष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है।

कुल मिलाकर, 2024-25 के ये आंकड़े केवल चंदे की रकम नहीं दिखाते, बल्कि वे यह भी दर्शाते हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है—जहां आर्थिक ताकत, कॉरपोरेट समर्थन और संसाधनों की उपलब्धता चुनावी रणनीति और राजनीतिक प्रभाव का अहम आधार बनती जा रही है।

## सरकारी सत्ता, संतों का चोला और सियासी साजिश: 'अश्लील वीडियो' विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया, बंगले से आश्रम तक फैले नेटवर्क पर उठे गंभीर सवाल

मुंबई/नासिक। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक ऐसे सनसनीखेज विवाद के केंद्र में खड़ी है, जिसने न केवल सत्ता के गलियारों को झकझोर दिया है, बल्कि धार्मिक आस्था के नाम पर खड़े किए गए तथाकथित साम्राज्यों की सच्चाई पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर स्वयंभू गॉडमैन अशोक खरात से जुड़ा कथित 'वीडियो कांड' अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दूसरी ओर राज्य सरकार के मंत्री नरहरि जिरवाल का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने से सियासी भूचाल आ गया है। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा 'डर्टी पॉलिटिक्स' का नैरेटिव खड़ा कर दिया है, जिसमें सत्ता, सेक्स, संत और साजिश—all एक खतरनाक मिश्रण के रूप में सामने आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि मंत्री नरहरि जिरवाल अपने सरकारी आवास पर एक किन्नर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है और मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। सवाल यह उठाया जा रहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि, जो जनता के टैक्स के पैसे से मिलने वाली सुविधाओं का उपयोग करता है, वह इस तरह के विवादों में घिरता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के लिए कितना बड़ा खतरा है।

हर्षवर्धन सपकाल ने इस पूरे प्रकरण को महाराष्ट्र की राजनीति के नैतिक पतन का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक वीडियो का मामला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की सच्चाई है, जहां जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपने आचरण से समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। वहीं विपक्ष के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे घटनाक्रम में ब्लैकमेलिंग की आशंका जताई है। उनके अनुसार, यह संभव है कि वीडियो को जानबूझकर वायरल कर राजनीतिक दबाव बनाने या किसी निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकारी आवास जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह से मर्यादा के खिलाफ हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बीच, मंत्री जिरवाल पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में उनके कार्यालय के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें अपने निजी सचिव को हटाना पड़ा था। अब इस नए विवाद ने उनकी राजनीतिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है, और उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि, अब तक इस पूरे मामले पर न तो मंत्री की ओर से और न ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे सस्पेंस और गहराता जा रहा है।

इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा गंभीर बनाता है नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला, जो अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि एक विशाल राजनीतिक-आर्थिक स्कैंडल का रूप ले चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार, अशोक खरात के ठिकानों से 100 से अधिक कथित आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं, जिनमें कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इन वीडियो के जरिए कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा नेटवर्क चलाए जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।

खरात के मामले में सबसे चौंकाने वाली बात उसकी कथित संपत्ति है, जो लगभग 1500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिन्नर स्थित 'श्री इशान्येश्वर देवस्थान ट्रस्ट' को 1.05 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी गई थी। उस समय जयकुमार रावल पर्यटन मंत्री थे। इस फंड का उपयोग मंदिर परिसर में सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जाना था, और शुरुआती 25 लाख रुपये खर्च भी किए जा चुके थे।

जांच में यह भी सामने आया है कि अशोक खरात के दरबार में कई बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का आना-जाना था। इसी राजनीतिक पहुंच और रसूख का फायदा उठाकर उसने अपने ट्रस्ट को सरकारी योजनाओं के तहत भारी फंड दिलवाया। उस समय उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, इसलिए उसे 'क्लीन' मानकर सहायता दी गई, लेकिन अब यही फंडिंग सरकार के लिए सवालों के घेरे में आ गई है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या सत्ता और संतों के बीच का यह गठजोड़ केवल आस्था तक सीमित है, या इसके पीछे एक गहरा आर्थिक और राजनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है? क्या 'वीडियो कांड' जैसे मामलों का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत बदनामी के लिए हो रहा है, या यह बड़े स्तर पर राजनीतिक नियंत्रण और ब्लैकमेलिंग का हथियार बन चुका है?

महाराष्ट्र की राजनीति में उठे इस दोहरे तूफान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गहराएगा। जांच एजेंसियों की कार्रवाई, राजनीतिक बयानबाजी और सामने आने वाले नए खुलासे तय करेंगे कि यह सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएगा या फिर एक बड़े सियासी और कानूनी भूकंप में तब्दील होगा। फिलहाल इतना तय है कि इस 'डर्टी पॉलिटिक्स' ने सत्ता और समाज दोनों के सामने आईना जरूर रख दिया है, जिसमें सच्चाई उतनी ही कड़वी है जितनी चौंकाने वाली।

## ऑटिज्म के नाम पर 'झूठे इलाज' पर सर्जिकल स्ट्राइक: सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्टेम सेल थेरेपी पर पूर्ण रोक, निजी क्लीनिकों की मनमानी पर लगा ब्रेक

नई दिल्ली। देश में गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज के नाम पर चल रहे कथित 'चमत्कारी इलाज' के कारोबार पर अब बड़ा प्रहार हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सख्त एडवायजरी जारी करते हुए ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियों के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है। 25 मार्च 2026 को जारी यह आदेश सीधे तौर पर उन निजी क्लीनिकों पर कार्रवाई का संकेत है, जो बिना वैज्ञानिक प्रमाण के इस थेरेपी के नाम पर मरीजों और उनके परिजनों से लाखों रुपये वसूल रहे थे।

यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और लगातार बढ़ती शिकायतें हैं। देशभर के कई मेट्रो और टियर-2 शहरों में ऐसे क्लीनिक सक्रिय थे, जो दावा करते थे कि वे स्टेम सेल तकनीक के जरिए ऑटिज्म को 'ठीक' कर सकते हैं। जबकि चिकित्सा विज्ञान में अब तक ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस दावे को सही ठहराता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्पष्ट कर दिया कि इन बीमारियों के लिए स्टेम सेल थेरेपी अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर है और इसे नियमित इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना न केवल भ्रामक है बल्कि खतरनाक भी।

दरअसल, स्टेम सेल थेरेपी एक उन्नत चिकित्सा तकनीक है, जिसमें शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित या बदलने की क्षमता होती है, लेकिन इसका उपयोग केवल कुछ विशेष और प्रमाणित बीमारियों तक ही सीमित है। इसी संदर्भ में NMC ने उन बीमारियों की सूची भी जारी की है, जिनमें इस थेरेपी का कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से रक्त और कैंसर से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं, जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायलोमा, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, साथ ही कुछ अन्य गंभीर स्थितियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जर्म सेल ट्यूमर और माइलोफाइब्रोसिस। इन बीमारियों में स्टेम सेल का उपयोग वर्षों के शोध और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद प्रमाणित हुआ है।

इस पूरे मामले में 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले ने निर्णायक भूमिका निभाई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण और वैधानिक मंजूरी के किसी भी मरीज को इस तरह की थेरेपी देना उसकी जान के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद डॉ. राजीव बहल ने NMC को पत्र लिखकर उन बीमारियों की सूची सौंपी, जिनमें स्टेम सेल थेरेपी को सीमित और नियंत्रित रूप में अनुमति दी गई है।

अब नए नियमों के तहत अगर कोई डॉक्टर, अस्पताल या क्लीनिक ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी का प्रचार करता है या इसका उपयोग करता है, तो यह सीधे-सीधे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, क्लीनिक को सील किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कदम केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए राहत है, जो अपने बच्चों के इलाज की उम्मीद में महंगे और अप्रमाणित इलाज के जाल में फंस जाते थे। ऑटिज्म जैसी स्थितियां जटिल होती हैं और इनके प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित थेरेपी, विशेष शिक्षा और व्यवहारिक उपचार की आवश्यकता होती है, न कि 'चमत्कारी इलाज' के नाम पर किए जाने वाले प्रयोग।

कुल मिलाकर, सरकार और शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के इस संयुक्त कदम ने यह साफ संदेश दे दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब किसी भी तरह की भ्रामक और अप्रमाणित तकनीकों के लिए कोई जगह नहीं है। यह फैसला न केवल चिकित्सा नैतिकता को मजबूत करता है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और अधिकारों को भी प्राथमिकता देता है, जो किसी भी विकसित स्वास्थ्य प्रणाली की बुनियाद होती है।

## राजस्थान में एक व्यापारी ने ईमानदारी दिखाते हुए गेहूं में मिले 15 लाख रुपये के गहने एक किसान को लौटा दिए

**(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।** आज के तेज रफ्तार कलियुग में रिश्तेदार संपत्ति, धन और गहनों के लिए माता-पिता को परेशान करना बंद नहीं करते, और कुछ मामलों में तो उनकी हत्या तक की खबरें समाचार चैनलों और अखबारों में आती रही हैं।

ऐसे में राजस्थान के खेरवा गांव में नीम के पेड़ पर मीठे पत्ते जैसी एक अनोखी कहानी सामने आई है। यह कहानी राजस्थान के पाली जिले के खेरवा गांव के एक अनाज व्यापारी की है, जिसने ईमानदारी की मिसाल कायम की। उसने गेहूं की बोरी से मिले 15 लाख रुपये के गहने किसान को लौटा दिए। कहानी यह है कि धीसाराम नाम के किसान ने अपने घर में गेहूं की फसल काटी थी और बोरियों को गेहूं से भरकर रख लिया था। घर में काम के दौरान बाहर से लोगों का आना-जाना लगा रहता था, इसलिए किसान की पत्नी ने गहनों को सुरक्षित रखने के लिए गेहूं की बोरियों से भरा एक बक्सा घर में रख दिया था।

लेकिन एक दिन, पत्नी की जानकारी के बिना, धिसाराम गेहूँ के बोरे लेकर पास के शहर गए और उन्हें एक अनाज व्यापारी को बेच दिया। जब मंगुखान ने उनसे 50-50 किलो के दो बोरे खरीदे, तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें गेहूँ का इतना बड़ा बोरा मिलेगा। 15 मार्च को, जब मंगुखान ने आटा पीसने के लिए गेहूँ निकाला, तो उसमें से एक स्टील का टिफिन डिब्बा निकला। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी पत्नी डिब्बा भूल गई होंगी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। जब मंगुखान की पत्नी ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी टिफिन के बारे में पता नहीं है, तो मंगुखान ने टिफिन खोला और देखा कि उसमें सोने के गहने थे। अगर ये उनकी पत्नी के नहीं थे, तो जरूर उस किसान धिसाराम के होंगे। मंगुखान ने बिना किसी लालच के गहनों से भरा डिब्बा धिसाराम को लौटा दिया। धिसाराम और उनकी पत्नी हैरान रह गए और पूरा गाँव इस घटना से अचंभित हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ईमानदारी मरी नहीं है, बल्कि आज भी जीवित है।

## ज़हर बना दूध: आंध्र प्रदेश में मिलावटी सप्लाई से 16 मौतें, मानवाधिकार उल्लंघन मानकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सख्त एक्शन, पूरे सिस्टम पर उठे सवाल

नई दिल्ली/पूर्वी गोदावरी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से सामने आई मिलावटी दूध की यह घटना केवल एक खाद्य मिलावट का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी भयावह त्रासदी बन चुकी है जिसने मानव जीवन की सुरक्षा, प्रशासनिक सतर्कता और खाद्य आपूर्ति तंत्र की विश्वसनीयता—तीनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। फरवरी के मध्य से शुरू हुई इस जहरीली सप्लाई की चपेट में आकर अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसे सीधे तौर पर "जीने के अधिकार" का उल्लंघन करार दिया है।

जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे और भी ज्यादा डराने वाले हैं। दूध में 'एथिलीन ग्लाइकोल' नामक अत्यंत जहरीला रसायन मिलाया गया था, जो सामान्यतः एंटी-फ्रीज़ के रूप में इस्तेमाल होता है। यह रसायन शरीर में पहुंचते ही धीरे-धीरे किडनी को पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है और इसके बाद 'मल्टी-ऑर्गन फेल्योर' की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह का जहर बेहद खतरनाक होता है क्योंकि शुरुआती लक्षण सामान्य फूड पॉइजनिंग जैसे लगते हैं, जिससे समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता और स्थिति तेजी से बिगड़ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र पूर्वी गोदावरी जिले का नरसापुरम गांव बताया जा रहा है, जहां स्थित वरलक्ष्मी मिल्क डेयरी से यह दूषित दूध सप्लाई किया जा रहा था। यह डेयरी लालाचेरुवु, चौदेश्वरन्नगर और स्वरूपनगर जैसे इलाकों के करीब 106 परिवारों को नियमित रूप से दूध पहुंचा रही थी। जैसे ही मामले की गंभीरता सामने आई, प्रशासन ने तुरंत डेयरी की सप्लाई पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके थे।

फरवरी के मध्य से ही प्रभावित लोगों में पेट दर्द, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी और पेशाब बंद हो जाने जैसे लक्षण दिखाई देने लगे थे। कई मामलों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मरीजों की किडनियां पूरी तरह फेल हो गईं। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में राजमहेंद्रवरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए डायलिसिस जैसे आपातकालीन उपचार का सहारा लिया। बावजूद इसके, 16 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, और कई अन्य अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। शुरुआती लक्षणों को सामान्य बीमारी मानकर नजरअंदाज करना और समय पर जहरीले तत्व की पहचान न कर पाना, इस त्रासदी को और भी गंभीर बना गया। अगर शुरुआती स्तर पर ही मिलावट का पता चल जाता, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और 14 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

## संपादकीय

### सख्ती व जवाबदेही से ही होगा समाधान

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की उस टिप्पणी को हमें एक गंभीर चेतावनी के रूप में लेना होगा, जिसमें कहा गया है कि प्रयागराज में गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि वह आचमन करने लायक भी नहीं रह गया है। एनजीटी का यह खुलासा इसलिये भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि कुछ ही माह बाद यानी जनवरी 2025 की पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। कुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और अखाड़ों की सक्रियता बढ़ गई है। महाकुंभ को लेकर देश ही नहीं विदेश में भी खूब चर्चा होती है। यदि गंगाजल की गुणवत्ता को लेकर ऐसे ही सवाल उठते रहे तो देश-दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सवाल इस बात को लेकर भी उठेंगे कि विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई अनेक महत्वाकांक्षी व भारी-भरकम योजनाओं के बावजूद गंगा को साफ करने में हम सफल क्यों नहीं हो पाए हैं। आखिर कौन है गंगा की यह हालत करने के गुनहगार? विडंबना देखिये कि तमाम सख्ती के बावजूद सैकड़ों खुले नाले गंगा में गंदा पानी गिरा रहे हैं। तमाम उद्योगों का अपशिष्ट पानी अनेक जगह गंगा में गिराया जा रहा है। वर्ष 2014 से गंगा की सफाई का महत्वाकांक्षी अभियान 'नमामि गंगे' शुरू किया गया था। बताया जाता है कि अब तक करीब चालीस हजार करोड़ की लागत से गंगा की सफाई की करीब साढ़े चार सौ से अधिक परियोजनाएं आरंभ भी की गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित शहरों में सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने, उद्योगों द्वारा बहाये जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिये शोधन संयंत्र लगाने, गंगा तटों पर वृक्षारोपण, जैव विविधता को बचाने, गंगा घाटों की सफाई के लिये काफी काम तो हुआ लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। जो हमें बताता है कि जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी और नागरिक अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं करेंगे, गंगा मैली ही रह जाएगी। सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं हैं।

दरअसल, लगातार बढ़ती जनसंख्या का दबाव और गंगा तट पर स्थित शहरों में योजनाबद्ध ढंग से जल निकासी व सीवरेज व्यवस्था को अंजाम न दिये जाने से समस्या विकट हुई है। गंगा को साफ करने के लिये जरूरी है कि स्वच्छता अभियान एक निरंतर प्रक्रिया हो। एक बार की सफाई निष्प्रभावी हो जाएगी यदि हम प्रदूषण के कारकों को जड़ से समाप्त नहीं करते। इसके लिये गंगा के तट वाले राज्यों में पर्याप्त जलशोधन संयंत्र युद्ध स्तर पर लगाए जाने चाहिए। साथ ही गंगा सफाई अभियान की नियमित निगरानी होनी चाहिए। इसमें आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाना चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है यह खाद्य शृंखला को संबल देने वाली तथा हमारी आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ी है। गंगा में अघुलनशील कचरा व अन्य अपशिष्ट डालने से रोकने के लिये जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। यदि जागरूकता व प्रेरित करने से बात नहीं बनती तो इसके लिये जुर्माने का प्रावधान भी होना चाहिए। साथ ही गंगा में जहरीला कचरा बहाने वाले उद्योगों पर भी आर्थिक दंड लगाना चाहिए। एक बात तो तय है कि सरकार के साथ जब समाज की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, गंगा का साफ होना असंभव जैसा हो जाएगा। गंगा सिर्फ बहती नदी नहीं है हमारे पुरखों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। गंगा मुक्तिकामी भी है। जीवनदायिनी भी है। ऐसे में केंद्र सरकार की नमामि गंगा परियोजना में राज्यों की भागीदारी और जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। साथ ही स्वच्छता परियोजना की निरंतर निगरानी की जानी भी जरूरी है ताकि प्रयासों का स्थायी लाभ गंगा को स्वच्छ बनाने में मिल सके। सही मायनों में आज गंगा के उद्धार के लिये हर भारतीय को भगीरथ जैसा दायित्व निभाना होगा। तभी सदियों से अविरल बह रही जीवनदायी गंगा की प्रतिष्ठा भी फिर से स्थापित हो सकेगी। फिर एनजीटी को यह न कहना पड़ेगा कि फलां जगह का गंगाजल आचमन करने लायक नहीं रह गया है।

# पाक की मध्यस्थता महज़ अवसरवाद

> पाक ट्रंप और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में कूटनीतिक प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता अभी भी संदिग्ध है और इसे अधिकतर सामरिक अवसरवाद के रूप में देखा जा रहा है।

पाकिस्तान आज एक रणनीतिक विरोधाभास में फंसा हुआ है—एक ओर वह अपनी पश्चिमी सीमा पर तालिबान के साथ बढ़ते संघर्ष में उलझा है, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में खुद को प्रस्तुत कर कूटनीतिक प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता अभी भी संदिग्ध है और इसे अधिकतर सामरिक अवसरवाद के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान अपने हालिया इतिहास के एक अत्यंत जटिल रणनीतिक दौर से गुजर रहा है। उसके पश्चिमी पड़ोस में तेजी से बदलते घटनाक्रम—ईरान में अस्थिरता और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ बिगड़ते रिश्ते—ने एक ऐसा भू-राजनीतिक दबाव पैदा कर दिया है, जिसे इस्लामाबाद न तो नजरअंदाज कर सकता है और न ही आसानी से संभाल सकता है। दशकों तक 'रणनीतिक गहराई' का जो ढांचा पाकिस्तान ने तैयार किया था, वह अब टूटता हुआ दिख रहा है। उसकी जगह अब अनिश्चितता, आतंकी प्रतिक्रिया और सीमावर्ती जोखिमों ने ले ली है।

पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा कभी शांत नहीं रही। ईरान से जुड़ी अस्थिरता इस्लामाबाद के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। ईरान केवल पड़ोसी ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार भी है। दोनों देशों की सीमा बलूचिस्तान के कठिन इलाकों से गुजरती है, जहां अलगाववादी समूह और तस्करी नेटवर्क सक्रिय रहे हैं। ईरान में किसी भी बड़े संकट से सीमा पार आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में हालात बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान की पुरानी ऊर्जा कमी ने ईरानी गैस को एक विकल्प बनाया है। हालांकि, प्रतिबंधों के कारण रुकी हुई ईरान–पाकिस्तान गैस पाइपलाइन अब भी एक संभावित समाधान मानी जाती है। लेकिन ईरान में अस्थिरता इस संभावना को और कमजोर कर सकती है और पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और जटिल बना सकती है।

इस समय पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी है और अतीत में सांप्रदायिक तनाव हिंसा में बदलता रहा है। ईरान से जुड़ा कोई भी लंबा संकट इन आंतरिक विभाजनों को भड़का सकता है और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

दशकों तक पाकिस्तान ने तालिबान के साथ संबंध इस उम्मीद में बनाए रखे कि काबुल में एक अनुकूल सरकार उसे रणनीतिक लाभ देगी। लेकिन 2021 में तालिबान की वापसी ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए। इसके विपरीत, संबंध लगातार बिगड़ते गए हैं। मुख्य विवाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की मौजूदगी है, जो पाकिस्तान में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगान तालिबान उसे संरक्षण देता है। सीमा पार हमले और तीखी बयानबाजी ने स्थिति को खतरनाक बना दिया है। जो संबंध कभी वैचारिक निकटता का प्रतीक था, वह अब अविश्वास और सीमित सैन्य टकराव में बदल चुका है। डूरंड रेखा का विवाद भी इस तनाव को और गहरा करता है। तालिबान इसे मान्यता देने से इंकार करता है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का मुद्दा मानता है। इन दबावों के बीच कुछ सीमित अवसर भी दिखाई देते हैं। यदि ईरान बाहरी संकटों में उलझता है तो बलूच सीमा पर उसका ध्यान कम हो सकता है। अफगानिस्तान की आर्थिक कमजोरी तालिबान को पाकिस्तान के साथ व्यावहारिक समझौते की ओर धकेल सकती है। पाकिस्तान क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, जिससे उसकी प्रासंगिकता कुछ हद तक बढ़े। लेकिन यह रणनीति जोखिमों से भरी है और इसके परिणाम पूरी तरह अनिश्चित हैं।

भारत के लिए यह स्थिति मिश्रित संकेत देती है। पाकिस्तान की पश्चिमी समस्याएं उसके संसाधनों पर दबाव डालती हैं, जिससे पूर्वी सीमा पर ध्यान कम हो सकता है। लेकिन यह अपने आप भारत के लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए भारत इन घटनाक्रमों को सावधानी और संतुलन के साथ देख रहा है।

चीन इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उसके निवेश ढांचे का अहम हिस्सा है। पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता इन योजनाओं के लिए खतरा है। चीन को चिंता है कि अफगानिस्तान के उग्रवादी नेटवर्क शिनजियांग को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वह इस्लामाबाद और काबुल के बीच संवाद को बढ़ावा देता है और आर्थिक सहयोग को स्थिरता का माध्यम मानता है। दरअसल, पाकिस्तान की चुनौती उसकी पुरानी रणनीति में है। दशकों तक उसने गैर-राज्य तत्वों का उपयोग किया, जो अब उसके लिए ही चुनौती बन गए हैं। यह स्पष्ट रूप से रणनीतिक 'ब्लोबैक' की स्थिति है। विकल्प केवल रणनीतिक पुनर्संतुलन है—क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक एकीकरण और उग्रवाद से दूरी। लेकिन यह परिवर्तन कितना संभव है, यह अभी अनिश्चित है।

## प्रेरणा

# राष्ट्र सर्वोपरि: त्याग, कर्तव्य और स्वतंत्रता की अमर गाथा

इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक प्रसंग दर्ज हैं, जो केवल घटनाएँ नहीं बल्कि आदर्श बनकर पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। जब भी राष्ट्र और व्यक्तिगत हितों के बीच चुनाव की स्थिति आती है, तब सच्चे देशभक्त वही होते हैं जो बिना किसी हिचकिचाहट के राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय घटित एक ऐसी ही प्रेरणादायक घटना हमें यह सिखाती है कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के आगे व्यक्तिगत संपत्ति, सुख-सुविधाएँ और निजी हित कितने छोटे हो जाते हैं। यह घटना उस समय की है जब अमेरिका ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। बोस्टन नगर उस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। ब्रिटिश सेना ने बोस्टन पर कब्जा कर लिया था और वहां अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। शहर के चारों ओर अमेरिकी सेनाओं ने घेरा डाल रखा था, जिससे ब्रिटिश सैनिक शहर के भीतर तो सुरक्षित थे, लेकिन उनके लिए रसद और आवश्यक आपूर्ति की भारी कमी उत्पन्न हो गई थी। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहने पर युद्ध की दिशा बदल सकती थी।

अमेरिकी सेना के प्रमुख जॉर्ज वाशिंगटन ने इस संकट को गंभीरता से समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि ब्रिटिश सेना को बोस्टन से बाहर निकालना है, तो कोई कठोर और निर्णायक कदम उठाना आवश्यक है। इसी सोच के तहत उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा कि बोस्टन नगर पर बमबारी की जाए, ताकि ब्रिटिश सेना को वहां से खदेड़ा जा सके। यह प्रस्ताव सुनते ही कांग्रेस के सभी सदस्य गहरे असमंजस में पड़ गए।

इस असमंजस का सबसे बड़ा कारण यह था कि बोस्टन केवल एक युद्धक्षेत्र नहीं था, बल्कि अनेक लोगों के जीवन, उनकी संपत्ति और उनके सपनों का केंद्र भी था। यदि बमबारी की जाती, तो शहर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता था, जिससे न केवल ब्रिटिश सेना को नुकसान होता, बल्कि अमेरिकी नागरिकों की भी भारी क्षति होती। इस स्थिति में कांग्रेस के सदस्यों के लिए निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो गया। सबसे अधिक दुविधा की स्थिति कांग्रेस के अध्यक्ष सर जॉन हैनकॉक के सामने थी। उनकी अधिकांश संपत्ति बोस्टन में ही स्थित थी। यदि बमबारी का निर्णय लिया जाता, तो उनकी वर्षों की मेहनत और जीवन भर की कमाई एक ही झटके में नष्ट हो सकती थी। यह एक ऐसा क्षण था, जहाँ एक व्यक्ति को अपने निजी हित और राष्ट्रहित के बीच चयन करना था।

लेकिन यहीं पर सच्चे नेतृत्व और देशभक्ति की परीक्षा होती है। सर जॉन हैनकॉक ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने समझ लिया कि उनके मौन रहने या अपने हितों के कारण निर्णय में देरी होने से राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। उन्होंने बिना किसी विलंब के अपने स्थान से उठकर कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित किया।

उनके शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सत्य है कि उनकी सारी संपत्ति बोस्टन में है और बमबारी से वह नष्ट हो सकती है। लेकिन यदि ब्रिटिश सेना को परास्त करने और देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बोस्टन को बमों से ध्वस्त कर दिया जाए, तो ऐसा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी संपत्ति के नष्ट होने का कोई दुख नहीं होगा, बल्कि गर्व और हर्ष होगा कि उनका व्यक्तिगत नुकसान राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए योगदान बन सका।

यह केवल एक वक्तव्य नहीं था, बल्कि एक जीवंत उदाहरण था कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। सर जॉन हैनकॉक ने यह सिद्ध कर दिया कि जब बात राष्ट्र की आती है, तो व्यक्तिगत हितों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उनका यह त्याग और निस्वार्थ भाव कांग्रेस के अन्य सदस्यों के लिए भी प्रेरणा बन गया और निर्णय लेने में उनकी दुविधा समाप्त हो गई।

इस घटना का महत्व केवल उस समय तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी यह हमें गहराई से प्रभावित करती है। यह हमें सिखाती है कि राष्ट्र निर्माण केवल युद्धभूमि में लड़ने से नहीं होता, बल्कि त्याग, साहस और सही निर्णय लेने की क्षमता से होता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के हित में सोचता है, तभी वह सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाता है।

आज के समय में, जब भौतिकवाद और व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ऐसे उदाहरण हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम भी ऐसे निर्णय लेने का साहस रखते हैं, जहाँ हमें अपने निजी हितों को त्यागकर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़े? यह प्रश्न हर नागरिक के सामने खड़ा है।

राष्ट्र के प्रति कर्तव्य केवल बड़े-बड़े त्याग करने तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन के छोटे-छोटे कार्यों में भी झलकता है। ईमानदारी से अपने काम को करना, कानून का पालन करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना—ये सभी राष्ट्रभक्ति के ही रूप हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है, तब वही लोग आगे आते हैं, जिनके भीतर त्याग और समर्पण की भावना होती है।

सर जॉन हैनकॉक की यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व का असली अर्थ क्या होता है। एक सच्चा नेता वही होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का साहस रखता है और अपने व्यक्तिगत हितों को त्यागकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका यह त्याग न केवल उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया।

अंततः यह कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल उसकी सेना या संसाधनों में नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र, उनके त्याग और उनके कर्तव्यबोध में होती है। जब हर नागरिक यह समझ लेता है कि राष्ट्र उससे बड़ा है, तब कोई भी शक्ति उस देश को कमजोर नहीं कर सकती।

सर जॉन हैनकॉक का यह त्याग हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसे बनाए रखने के लिए हमें समय-समय पर अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़ता है। यही सच्ची देशभक्ति है, यही राष्ट्रधर्म है, और यही वह भावना है जो किसी भी देश को महान बनाती है।

# रामराज्य को साकार करने की रूपरेखा

रामनवमी का पावन पर्व भारतीय जनमानस के लिए केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग और सत्य की विजय का उत्सव है। यह पर्व हमें एक ऐसे आदर्श समाज की स्मृति दिलाता है, जिसे रामराज्य के रूप में युगों-युगों से एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ माना गया है। नवंबर 2025 में अयोध्या में 'धर्म ध्वजारोहण' के अवसर पर जो संवाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के सम्मुख रखा गया, वह न केवल भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक था, बल्कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सुस्पष्ट नैतिक रोडमैप भी था।

इस विमर्श का सबसे गहरा पक्ष 'विभीषण गीता' का वह प्रसंग था, जिसके माध्यम से प्राचीन मानवीय मूल्यों को आधुनिक सुशासन और राष्ट्र-निर्माण से जोड़ा गया। यह संवाद उस गंभीर क्षण पर होता है, जब रावण को अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल रथ पर सवार देखकर विभीषण विचलित हो जाते हैं। इसके उत्तर में जिस 'धर्मरथ' का वर्णन किया गया, वह भौतिक संसाधनों पर आंतरिक गुणों और चारित्रिक सुदृढ़ता की श्रेष्ठता का उद्घोष है।

किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए साहस और संयम का संतुलन अनिवार्य है। धर्मरथ के दो पहिए 'शौर्य' और 'धैर्य' इसी संतुलन को दर्शाते हैं। समकालीन संदर्भों में 'शौर्य' का अर्थ नीतिगत निर्णय लेने का साहस और चुनौतियों के सामने अडिग रहने की इच्छाशक्ति है। वहीं 'धैर्य' का अर्थ है उन सुधारों के दीर्घकालिक परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक संकटों के समय विचलित न होना। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र का रथ इन दो गुणों के संतुलन से चले।

धर्मरथ की ध्वजा 'सत्य' और 'शील' का प्रतीक है। आधुनिक सुशासन में 'सत्य' का अर्थ पारदर्शिता और जवाबदेही है। जब व्यवस्था में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होता और प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक हित में लिया जाता है, तब सत्य की ध्वजा ऊंची रहती है। आज 'शील' या सदाचार का अर्थ नागरिकों और लोकसेवकों का वह आचरण है, जो मर्यादा के अनुकूल हो। यह आचरण ही किसी देश की छवि को वैश्विक पटल पर स्थापित करता है। बल, विवेक, दम और परहित राष्ट्र की चतुर्मुखी शक्ति है।

धर्मरथ को खींचने वाले ये चार 'घोड़े' राष्ट्र की शक्ति और उसके उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। जहां 'बल' राष्ट्र की सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, वहीं 'शक्ति' संग विवेक का होना अनिवार्य है। आज के युग में विवेक का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक का मानवीय कल्याण के लिए उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति जिम्मेदारी 'दम' का ही आधुनिक रूप है। 'परहित' भी महत्वपूर्ण है। विकास की सार्थकता तभी है, जब वह समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इन चार घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगाम क्षमा, कृपा और समता की रस्सियां हैं। बिना सामाजिक न्याय और समानता के विकास का रथ अनियंत्रित हो सकता है। समावेशी विकास का अर्थ ही यही है कि समाज का हर वर्ग समान रूप से सशक्त बने।

अयोध्या के प्रसंग में 'कोविदार' वृक्ष के प्रतीक का उल्लेख महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में कोविदार का चिह्न अयोध्या की सेना और राज्य की पहचान था। यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी जड़ों से कट जाता है, तो उसका वैभव इतिहास में दब जाता है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी भाषाई विविधता, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राचीन ज्ञान तंत्र पर गर्व करता हो। मानसिक दासता से मुक्ति और अपनी पहचान की पुनर्स्थापना ही राष्ट्र के आत्मविश्वास को लौटाती है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी है। यह युवा शक्ति ही वह सारथी है, जो 2047 के संकल्प को सिद्ध करेगी।

तकनीक, स्टार्टअप्स और नवाचार के माध्यम से आज के युवा भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। युवाओं की ऊर्जा को कर्तव्य बोध के साथ जोड़ना ही 'धर्मरथ' को सही दिशा में ले जाने का मार्ग है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा, वह हमारे लिए केवल एक संख्या ही नहीं, बल्कि एक पड़ाव होगा। विभिन्न शोधों के अनुसार भारत का लक्ष्य 30-35 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ-साथ गरीबी को न्यूनतम स्तर पर लाने और प्रति व्यक्ति आय को विकसित देशों के समकक्ष पहुंचाने का है। यह लक्ष्य केवल सरकारी नीतियों से संभव नहीं। इसके लिए 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक भागीदारी और 'धर्मरथ' के मूल्यों का व्यक्तिगत जीवन में समावेश आवश्यक है।

प्रभु श्रीराम का जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि पथ 'धर्म' (कर्तव्य) का हो, तो विजय निश्चित है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कार्य को राष्ट्र के प्रति एक आहुति मानेगा और 'परहित' को अपना ध्येय बनाएगा, तभी हम सच्चे अर्थों में रामराज्य की उस परिकल्पना को साकार कर पाएंगे जहां 'बैर न बिग्रह आस न त्रासा' (न शत्रुता, न भय और न ही दुख)। यही वह समय है जब हमें अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है, ताकि 2047 का भारत न केवल समृद्ध हो, बल्कि मानवता के लिए शांति और न्याय का प्रदाता बने।

## अभियान

# जाखू पर्वत की रहस्यमयी कथा: जहां आज भी जीवित हैं हनुमान के चरणों के दिव्य साक्ष्य

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनेक स्थल हैं, जहां आस्था केवल विश्वास नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार के अनगिनत चमत्कारी और पौराणिक स्थलों का घर है। इन्हीं में एक अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यमयी स्थल है Jakhu Temple, जो अपनी अद्भुत कथा, विशाल प्रतिमा और दिव्य ऊर्जा के लिए जाना जाता है।

Shimla की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2,438 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। जाखू हिल की चोटी तक पहुंचना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। जैसे-जैसे श्रद्धालु ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे वातावरण बदलता जाता है—नीचे का शहरी शोर धीरे-धीरे गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है शांति, ठंडी हवाएं और देवदार के पेड़ों की सुगंध। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है।

इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यहां स्थापित भगवान Hanuman की विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा इतनी ऊंची है कि दूर से ही श्रद्धालुओं को अपने दर्शन दे देती है। लाल रंग की यह भव्य मूर्ति शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहां सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।

जाखू मंदिर की सबसे चर्चित मान्यता हनुमान जी के चरणचिह्नों से जुड़ी हुई है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मंदिर परिसर में आज भी उनके पदचिन्ह सुरक्षित हैं। इन पदचिन्हों को लेकर लोगों में गहरी श्रद्धा है और वे इन्हें केवल पत्थर पर बने निशान नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इस कथा का संबंध सीधे Ramayana से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार है।

पौराणिक कथा के अनुसार, जब लंका में भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी दौरान Lakshmana मेघनाथ के शक्तिबाण से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी और उन्हें बचाने के लिए तुरंत संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। वैद्य सुशेन ने बताया कि यह औषधि केवल हिमालय के द्रोणगिरि पर्वत पर ही मिल सकती है और इसे रात के समय ही लाना होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को चुना। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे कुछ ही समय में उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले गए। इसी यात्रा के दौरान उनकी नजर जाखू पर्वत पर पड़ी।

उस समय यह पर्वत एक तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध था, जहां एक यक्ष ऋषि गहन साधना में लीन थे। हनुमान जी ने सोचा कि यहां उन्हें संजीवनी बूटी के बारे में सही जानकारी मिल सकती है, इसलिए वे इस पर्वत पर उतरे। जब उन्होंने इस पर्वत पर कदम रखा, तो उनके दिव्य भार के कारण यह पहाड़ी थोड़ी धंस गई। कहा जाता है कि इसी कारण आज भी जाखू हिल ऊपर से कुछ समतल दिखाई देती है।

हनुमान जी ने यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऋषि ने उन्हें सही दिशा दिखाई और हनुमान जी ने थोड़ी देर विश्राम भी किया। उस समय ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि लौटते समय वे उन्हें दर्शन अवश्य दें। हनुमान जी ने यह वचन स्वीकार किया और तुरंत अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए।

जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में उनका सामना कालनेमि नामक राक्षस से हुआ। कालनेमि ने उन्हें रोकने और भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। इस संघर्ष के कारण उन्हें थोड़ी देरी हो गई और वे सीधे लंका की ओर चले गए। इस कारण वे यक्ष ऋषि को दिए गए वचन के अनुसार तुरंत दर्शन नहीं दे पाए।

यक्ष ऋषि इस बात से अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने हनुमान जी का ध्यान करना शुरू किया। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी गहन थी कि हनुमान जी पुनः जाखू पर्वत पर प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। उसी समय वहां हनुमान जी की एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे ऋषि ने स्थापित किया। यही स्थान आगे चलकर जाखू मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

मान्यता है कि जब हनुमान जी इस पर्वत पर उतरे थे, तब उनके पैरों के निशान यहां अंकित हो गए थे। ये पदचिन्ह आज भी मंदिर परिसर में देखे जा सकते हैं। श्रद्धालु इन पदचिन्हों को अत्यंत श्रद्धा से पूजते हैं और मानते हैं कि इनमें दिव्य शक्ति समाहित है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

जाखू मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत उदाहरण है। यहां से शिमला शहर का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। चारों ओर फैले देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण इस स्थान को और भी विशेष बना देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्रकृति स्वयं पूजा कर रही हो।

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में बंदर भी पाए जाते हैं, जिन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है। ये बंदर यहां के वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। श्रद्धालु इन्हें प्रसाद देते हैं और इनके साथ एक अनोखा संबंध अनुभव करते हैं। हालांकि, यहां आने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बंदर कभी-कभी शरारती भी हो सकते हैं। आज के समय में जाखू मंदिर एक प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल बन चुका है। देश-विदेश से हजारों लोग यहां आते हैं और इस दिव्य स्थान का अनुभव करते हैं। यहां पहुंचने के लिए अब रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी आसान हो गई है।

इस मंदिर से जुड़ी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण में अपार शक्ति होती है। यक्ष ऋषि की तपस्या और हनुमान जी की कृपा यह दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं करते।

अंततः जाखू मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है, जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलकर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं। यहां के चरणचिन्ह हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे पौराणिक इतिहास की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनमें कितनी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। यह स्थान हर श्रद्धालु के हृदय में विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, जो जीवनभर उसके साथ बनी रहती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# पुलिस कस्टडी से 'गायब' ड्रग्स पर सियासी भूचाल, गुजरात में नशे और भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला

गुजरात की राजनीति उस समय अचानक गरमा गई जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कस्टडी से कथित तौर पर गायब हुए भारी मात्रा में ड्रग्स के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जामनगर में आयोजित विजय विश्वास सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ मंच साझा करते हुए केजरीवाल ने इस पूरे मामले को न केवल कानून व्यवस्था की विफलता बताया, बल्कि इसे एक बड़े संगठित भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए करीब 2300 किलो से अधिक ड्रग्स के "चूहों द्वारा खा जाने" जैसी बातें जनता की बुद्धिमत्ता का अपमान हैं और यह दर्शाता है कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

केजरीवाल ने अपने भाषण में बेहद तीखे अंदाज में सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिस कस्टडी जैसी सुरक्षित जगह से 35 प्रतिशत ड्रग्स कैसे गायब हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यह ड्रग्स तस्करों तक पहुंचाए गए होंगे, जिससे समाज में नशे का जहर और तेजी से फैल रहा है। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि राज्य के भीतर नशे का कारोबार किस हद तक संगठित हो चुका है और इसके पीछे सत्ता में बैठे लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

सभा के दौरान उन्होंने गुजरात की वर्तमान स्थिति पर भी विस्तार से बात करते हुए कहा कि एक समय देश का सबसे समृद्ध और अग्रणी राज्य माना जाने वाला गुजरात आज कई मामलों में पिछड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों में सत्ता में रही बीजेपी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल और अस्पतालों की हालत खराब है, सड़कों और पुलों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वे कुछ ही समय में टूट जाते हैं, और आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है।

केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि गुजरात में ये दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। उनके मुताबिक, सरकारी ठेकों से लेकर नीतिगत फैसलों तक, दोनों के बीच एक गुप्त समझौता है, जिससे जनता को कोई मजबूत विकल्प नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बीजेपी को हटाना ही नहीं चाहती क्योंकि दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि वर्षों से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका। पंजाब का उदाहरण देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वहां भी 2022 से पहले हालात खराब थे, लेकिन जनता ने बदलाव का फैसला लिया और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर सत्ता में लाया। उन्होंने दावा किया कि आज पंजाब में किसानों को दिन में आठ घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है, सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है और किसानों को उनकी फसल का भुगतान उसी दिन उनके खातों में मिल जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने हर परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लागू किया है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी बड़े अस्पतालों में इलाज करवा सकता है।

वहीं भगवंत सिंह मान ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में लंबे समय से सत्ता में बैठी सरकार ने किसानों और आम जनता की मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी का पानी हर खेत तक पहुंचाने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य भी समय पर नहीं मिलता। उन्होंने पंजाब में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अब अधिकांश खेतों तक नहरी पानी पहुंच रहा है और किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

सभा के दौरान दोनों नेताओं ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि गुजरात की जनता के पास अब एक नया राजनीतिक विकल्प मौजूद है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करते हुए जनता से समर्थन की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और राज्य के संसाधनों का उपयोग सीधे जनता के हित में किया जाएगा।

पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि गुजरात में आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला और भी तेज होने वाला है। ड्रग्स कांड जैसे गंभीर मुद्दे ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन आरोपों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और जनता इन दावों को किस नजर से देखती है, क्योंकि यही तय करेगा कि गुजरात की राजनीति आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

# कच्चे तेल की उछाल से देश में ईंधन महंगा, 6,967 पेट्रोल पंपों पर बढ़े दाम, निजी कंपनी के फैसले से आम जनता पर बोझ

नई दिल्ली से सामने आई इस खबर ने आम आदमी की जेब पर एक और दबाव बढ़ा दिया है, जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का असर अब सीधे देश के ईंधन बाजार में दिखने लगा है। इसी क्रम में Nayara Energy ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने नेटवर्क के हजारों पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी देशभर में उसके द्वारा संचालित 6,967 पेट्रोल पंपों पर लागू की गई है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि यह फैसला अचानक नहीं बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक, 28 फरवरी के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत तक का उछाल आया है, जिसने तेल कंपनियों की लागत को काफी बढ़ा दिया है। ऐसे में निजी कंपनियों के सामने या तो घाटा सहने की मजबूरी थी या फिर कीमतों में इजाफा करने का विकल्प, और Nayara Energy ने दूसरा रास्ता चुना। कंपनी का मानना है कि बढ़ती लागत को पूरी तरह खुद वहन करना संभव नहीं है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी हो गया था।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह है कि सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक अपने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां फिलहाल बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाते हुए खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अभी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दिखा है, क्योंकि इन सरकारी कंपनियों का बाजार में करीब 90 प्रतिशत हिस्सा है।

वहीं निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियां भी इस स्थिति को करीब से देख रही हैं। Reliance Industries और बीपी के संयुक्त उद्यम Jio-bp ने फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, हालांकि उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी बनी रहती है, तो आने वाले समय में ये कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी करने को मजबूर हो सकती हैं।

ईंधन कीमतों में यह बढ़ोतरी पूरे देश में एक समान नहीं दिखेगी, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स का ढांचा अलग है। इसी वजह से कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत 5 रुपये से अधिक यानी करीब 5.30 रुपये प्रति लीटर तक भी बढ़ सकती है। इससे परिवहन लागत बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है, जिसका असर धीरे-धीरे अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

वैश्विक स्तर पर हालात भी इस बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वजह बने हुए हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और खाड़ी क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने से तेल के परिवहन पर असर पड़ा है, जिससे लागत और बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखना और भी मुश्किल हो जाएगा।

इस बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में पिछले चार वर्षों से खुदरा ईंधन कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है। अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं, जिसके चलते सरकारी कंपनियां समय-समय पर बढ़ती लागत का बोझ खुद वहन करती रही हैं। हालांकि हाल ही में इन कंपनियों ने प्रीमियम या हाई-ग्रेड पेट्रोल के दाम में लगभग 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे संकेत मिल रहा है कि दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों को लेकर स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी नहीं आई, तो न सिर्फ निजी कंपनियां बल्कि सरकारी कंपनियां भी कीमतों में बदलाव करने को मजबूर हो सकती हैं, जिसका सीधा असर देश की आम जनता और महंगाई पर पड़ेगा।

# 500 फीट ऊंचे पर्वत पर 131 फीट के 'बजरंगबली' का दिव्य उदय, रामनवमी पर नाथद्वारा में भक्ति आस्था और शिल्प का अद्भुत संगम

राजस्थान के राजसमंद जिले का पावन नगर नाथद्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर उस समय एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र बन गया, जब गिरिराज पर्वत की ऊंचाइयों पर 131 फीट ऊंची 'बजरंगबली' की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। यह दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं था, बल्कि श्रद्धा, समर्पण, वास्तुकला, तकनीक और दिव्यता का ऐसा संगम था, जिसने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बना दिया। लगभग 500 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थापित यह विशाल प्रतिमा दूर-दूर तक अपनी दिव्य आभा बिखेरती नजर आती है, मानो स्वयं संकटमोचन इस पावन धरा पर विराजमान होकर भक्तों का आह्वान कर रहे हों। इस भव्य आयोजन में देशभर से संत-महात्मा, आध्यात्मिक गुरु और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतिमा का उद्घाटन गुरुदेव राकेशजी, राजचंद्र मिशन के संतों और गोस्वामी विशाल बाबा के करकमलों से संपन्न हुआ। उस क्षण का वातावरण भक्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण था, जहां "जय श्रीराम" और "जय हनुमान" के उद्घोषों के बीच पूरा क्षेत्र एक दिव्य स्पंदन से भर गया। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था, मन में श्रद्धा और वातावरण में भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने इस आयोजन को साधारण से असाधारण बना दिया।

यह प्रतिमा केवल आकार में विशाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी भावना और प्रतीकात्मकता भी अत्यंत गहरी है। इस अद्भुत संरचना में हनुमान को एक विनम्र, भक्त और सेवक रूप में दर्शाया गया है, जहां वे हाथ जोड़कर श्रीनाथजी की ओर नतमस्तक हैं। यह दृश्य भक्ति की उस सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है, जहां शक्ति और विनम्रता एक साथ विद्यमान होती हैं। यह प्रतिमा न केवल हनुमानजी की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि सच्ची शक्ति सेवा और समर्पण में निहित होती है।

इस विराट प्रतिमा का निर्माण लगभग तीन वर्षों की सतत साधना, तकनीकी कुशलता और अटूट विश्वास का परिणाम है। प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत ने इसे आकार दिया, जबकि इस पूरे प्रकल्प को साकार करने में गिरीश भाई शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने इसे एक "आध्यात्मिक संकल्प" बताया, जो गुरुदेव से मिली प्रेरणा और आत्मबल के माध्यम से संभव हो पाया। उनके अनुसार, यह केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि एक भक्त की अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा का साकार रूप है।

प्रतिमा के निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग और पारंपरिक शिल्पकला का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। इसमें लगभग 115 टन स्टील और 40 टन ग्लास रिइंफोर्स्ड फाइबर (GRF) का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी संरचना को मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया गया है। पूरी प्रतिमा M30 ग्रेड प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से बनाई गई है, जो इसे वर्षों तक अडिग बनाए रखने में सक्षम है। इसकी नींव को भी उतनी ही सुदृढ़ता के साथ तैयार किया गया है जितनी इसकी ऊपरी संरचना को, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार का इस पर कोई प्रभाव न पड़े। निर्माण के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया। हर चरण में उपयोग की गई सामग्री का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया गया, जिससे इसकी दीर्घायु और मजबूती सुनिश्चित हो सके। साथ ही, प्रतिमा को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसके हिस्सों की संख्या कम रहे, जिससे इसके कमजोर होने की संभावना कम हो और यह लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे।

इस प्रतिमा की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है इसका सुनहरा आभामंडल। इसके लिए विशेष गोल्डन कोटिंग थाईलैंड से मंगवाई गई है, जो इसे दिव्यता के साथ-साथ टिकाऊपन भी प्रदान करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोटिंग 40 से 50 वर्षों तक अपनी चमक बनाए रखेगी और मौसम के किसी भी प्रभाव—चाहे वह तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या भीषण गर्मी—का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सूर्य की किरणों के साथ यह प्रतिमा जब चमकती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया हो।

इस पूरे आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। गिरीश भाई शाह ने स्पष्ट किया कि यह स्थान हर भक्त के लिए समान रूप से खुला रहेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से क्यों न हो। यह निर्णय इस पूरे प्रकल्प की मूल भावना—सेवा, समर्पण और समानता—को और भी मजबूत बनाता है।

रामनवमी के दिन हुआ यह लोकार्पण नाथद्वारा को वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर एक नई पहचान देने वाला साबित हो सकता है। नाथद्वारा पहले ही श्रीनाथजी मंदिर के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है, और अब यह 131 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा इसे और भी आकर्षक और महत्वपूर्ण बना देगी। आने वाले समय में यह स्थल न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बन सकता है।

जब गिरिराज पर्वत की ऊंचाइयों पर खड़े होकर कोई इस प्रतिमा को निहारता है, तो उसे केवल एक विशाल संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती रहेगी कि श्रद्धा, संकल्प और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह, 131 फीट ऊंचे 'बजरंगबली' का यह दिव्य प्राकट्य न केवल एक ऐतिहासिक निर्माण है, बल्कि यह भारतीय आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का एक अमर प्रतीक बन चुका है।

# रामनवमी पर अयोध्या में आस्था और राजनीति का संगम, रामलला के दरबार पहुंचे दिग्विजय सिंह, बोले—कभी नहीं किया मंदिर का विरोध

रामनवमी के पावन पर्व पर अयोध्या एक बार फिर आस्था, भक्ति और राजनीतिक संकेतों का केंद्र बन गई, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भगवान श्रीराम की नगरी पहुंचे और रामलला के दरबार में मत्था टेककर देश की सुख-समृद्धि की कामना की। उनका यह दौरा केवल एक धार्मिक यात्रा भर नहीं रहा, बल्कि इसके कई गहरे राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब राम मंदिर का मुद्दा लंबे समय तक देश की राजनीति के केंद्र में रहा है और दिग्विजय सिंह स्वयं कई बार इस विषय को लेकर विवादों में रहे हैं।

अयोध्या पहुंचने पर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ रामलला के दर्शन किए। मंदिर परिसर में बिताए गए समय के दौरान उन्होंने गहरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की और प्रभु श्रीराम से देश में शांति, सौहार्द और खुशहाली बनाए रखने की प्रार्थना की। इसके पश्चात उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर भी पूजा की, जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है।

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उनका रुख काफी स्पष्ट और संतुलित नजर आया। राम मंदिर निर्माण के विरोध को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में 1 लाख 11 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग भी दिया था। उनके अनुसार, उनके विचारों को लेकर जो धारणा बनाई गई है, वह राजनीतिक कारणों से पैदा हुई है और वास्तविकता उससे अलग है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक दलों के बीच राम मंदिर को लेकर अपनी-अपनी छवि को मजबूत करने की होड़ भी देखी जा रही है।

दिग्विजय सिंह ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि वे इस यात्रा को पूरी तरह धार्मिक मानते हैं और इसी कारण उन्होंने किसी भी राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी का दिन उनके लिए केवल भक्ति और आत्मिक शांति का अवसर है, न कि राजनीतिक बयानबाजी का मंच। हालांकि उनके इस बयान को भी कई विश्लेषक एक रणनीतिक संतुलन के रूप में देख रहे हैं, जहां वे धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक विवादों से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त कीं, वह उनकी व्यक्तिगत आस्था को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में उपस्थित होकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई और उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति हुई। उन्होंने भगवान श्रीराम से प्रार्थना की कि देश में भाईचारा बना रहे, समाज में एकता मजबूत हो और हर व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि आए। यह संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में समाज में सामंजस्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद यह उनका पहला अयोध्या दौरा है। इससे पहले वे कई बार इस मुद्दे पर दिए गए बयानों को लेकर आलोचना का सामना कर चुके हैं। ऐसे में रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर अयोध्या पहुंचना और खुले तौर पर अपनी आस्था व्यक्त करना, एक तरह से उनकी छवि को संतुलित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अयोध्या अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह देश की राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। यहां आने वाले हर बड़े नेता का दौरा अपने आप में एक संदेश लेकर आता है—चाहे वह आस्था का हो, जनसंपर्क का या फिर राजनीतिक रणनीति का। दिग्विजय सिंह का यह दौरा भी इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, जहां धार्मिक आस्था और राजनीतिक संकेत दोनों एक साथ चलते नजर आते हैं।

# सोना वायदा 3175 रुपये और चांदी वायदा 14090 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 427 रुपये का ऊछाल

**(जीएनएस)**। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 118480.18 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 7765.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 110714.73 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 798.24 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 6043.69 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 139800 रुपये के भाव पर खूलकर, 141433 रुपये के दिन के उच्च और 139800 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 144097 रुपये के पिछले बंद के सामने 3175 रुपये या 2.2 फीसदी लुढ़ककर 140922 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 2450 रुपये या 2.12 फीसदी घटकर 113217 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 294 रुपये या 2.03 फीसदी घटकर 14171 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 144000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 144000 रुपये और नीचे में 140300 रुपये पर पहुंचकर, 3441 रुपये या 2.38 फीसदी घटकर 140897 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 141003 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 141777 रुपये और नीचे में 140400 रुपये पर पहुंचकर, 144036 रुपये के पिछले बंद के सामने 3435 रुपये या 2.38 फीसदी घटकर 140601 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 225441 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 225441 रुपये और नीचे में 220744 रुपये पर पहुंचकर, 234834 रुपये के पिछले बंद के सामने 14090 रुपये या 6 फीसदी औंधकर 220744 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 14135 रुपये या 5.92 फीसदी गिरकर 224500 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 14226 रुपये या 5.96 फीसदी गिरकर 224650 रुपये प्रति किलो हुआ।

**▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 7765.45 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 110714.73 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 6043.69 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार**

मेटल वर्ग में 620.76 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 7.1 रुपये या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 1121.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.65 रुपये या 0.53 फीसदी की बढ़त के साथ 310.95 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.9 रुपये या 0.57 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 334.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 1.65 रुपये या 0.85 फीसदी घटकर 191.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 811.26 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8838 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8944 रुपये और नीचे में 8838 रुपये पर पहुंचकर, 427 रुपये या 5.02 फीसदी की तेजी के संग 8926 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 429 रुपये या 5.05 फीसदी की तेजी के संग 8929 रुपये प्रति बैरल हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 277.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 279.2 रुपये के दिन के उच्च और 274.2 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 30 पैसे या 0.11 फीसदी के सुधार के साथ 277.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 50 पैसे या 0.18 फीसदी चढ़कर 278 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 3476.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 2567.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 431.86 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 127.83 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 1.58 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 59.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 559.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 249.52 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8588 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 56391 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28501 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 367841 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 64720 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7085 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18745 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 71038 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17631 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26156 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 223 रुपये की बढ़त के साथ 834.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 65 पैसे के सुधार के साथ 19.7 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 925 रुपये की गिरावट के साथ 3930 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6356.5 रुपये की गिरावट के साथ 261.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.35 रुपये की गिरावट के साथ 16.3 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 53.2 रुपये की गिरावट के साथ 139 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 15 पैसे की नरमी के साथ 17 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 368.5 रुपये की बढ़त के साथ 1781 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 343.5 रुपये की बढ़त के साथ 653 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.31 रुपये की बढ़त के साथ 20.45 रुपये हुआ।

# गुजरात का 'बनास BIO-CNG' मॉडल बन रहा कचरे से कंचन और ग्रामीण समृद्धि का नया राष्ट्रीय मानक

- BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य बजट में किया 60 करोड़ का प्रावधान
- BIO-CNG गैस और जैविक उर्वरक की बिक्री से प्रति संयंत्र सालाना लगभग 12 करोड़ राजस्व सृजन का अनुमान
- परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, 'ग्रीन गुजरात' के संकल्प को मिलेगा बल

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वेस्ट टू वेल्थ', आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा के विजन को धरातल पर उतारते हुए गुजरात का विकास मॉडल अब एक सफल राष्ट्रीय मिसाल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में विकसित बनास BIO-CNG प्लांट मॉडल को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय और केंद्रीय सहकारिता विभाग के संयुक्त प्रयासों से देश के लगभग 15 राज्य अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बनास डेयरी द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट गोबर जैसे पारंपरिक अपशिष्ट को स्वच्छ ईंधन और जैविक उर्वरक में बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रहा है।

### BIO-CNG क्षेत्र को गुजरात सरकार का बजटीय समर्थन, 60 करोड़ का आवंटन

गुजरात सरकार ने इस अभिनव पहल की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए BIO-CNG क्षेत्र को अपनी बजटीय प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों द्वारा नए प्लांट स्थापित करने के लिए 60 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है। इस बजटीय सहायता का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत राज्य में चरणबद्ध तरीके से लगभग 10 BIO-CNG प्लांट स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है।

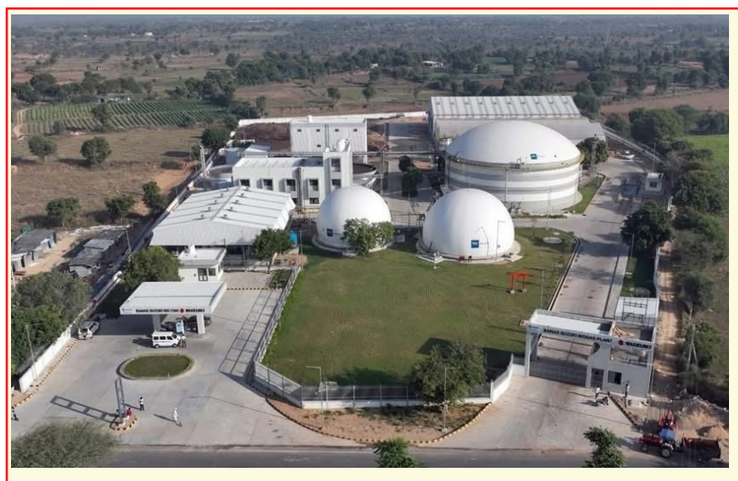

### पशुपालक किसानों के लिए BIO-CNG प्लांट बन रहा अतिरिक्त आय का स्रोत

बनासकांठा में स्थापित BIO-CNG संयंत्रों के दायरे में लगभग 20 किलोमीटर के आसपास स्थित 20-25 गांवों के पशुपालक परिवार जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से गोबर की आपूर्ति करते हैं। किसानों को गोबर के बदले 1 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जिससे अनुमानित 400-450 पशुपालक परिवारों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। गोबर संग्रहण और परिवहन के लिए लगभग 13 ट्रैक्टर-ट्रॉली उपयोग में लाई जा रही है, जो लगभग 4-4 मीट्रिक टन प्रति ट्रिप क्षमता के साथ गोबर को संयंत्र तक पहुंचाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही नहीं, यह संयंत्र बहु-उत्पाद आधारित आर्थिक मॉडल पर कार्य करता है, जिसके तहत प्रतिदिन लगभग 1,800 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस (CNG) का उत्पादन होता है, जिसे करीब 75 प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही लगभग 25 मीट्रिक टन ठोस जैविक उर्वरक और 75 मीट्रिक टन तरल जैविक उर्वरक का उत्पादन भी होता है, जिन्हें क्रमशः लगभग 6 प्रति किलोग्राम और 0.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इन तीनों उत्पादों से संयंत्र को प्रतिदिन लगभग 3 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है, जो वार्षिक रूप से करीब 12 करोड़ तक पहुंच सकता है।

### किसान, उद्योग और पर्यावरण का 'विन-विन' कॉम्बिनेशन है बनास BIO-CNG प्लांट मॉडल

बनासकांठा में 40 मीट्रिक टन प्रतिदिन गोबर प्रसंस्करण क्षमता वाला बनास BIO-CNG प्लांट पिछले 6 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित एक प्रूवन मॉडल है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर बनासकांठा में 5 विशाल BIO-CNG प्लांट्स शुरू करने पर काम जारी है। वर्तमान में नियोजित 5 प्लांट्स में से 2 संयंत्रों ने परिचालन शुरू कर दिया है, जबकि तीसरा प्लांट अपने पूर्णता के अंतिम चरण में है। प्रत्येक प्लांट प्रतिदिन लगभग 100 मीट्रिक टन (1 लाख किलो) गोबर को वैज्ञानिक पद्धति से प्रोसेस करता है। लगभग 50-55 करोड़ की निवेश लागत से निर्मित यह संयंत्र आधुनिक तकनीक और इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और कैसे पर्यावरण संरक्षण, किसानों की समृद्धि और औद्योगिक प्रगति तीनों एक साथ संभव है।

### BIO-CNG प्लान्ट्स से राज्य सरकार के 'ग्रीन गुजरात' के संकल्प को मिल रहा बल

गुजरात की यह अभिनव परियोजना न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। यह मॉडल प्रतिवर्ष लगभग 6,750 टन $CO_2e$ (कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखता है, जो जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती के खिलाफ गुजरात की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। स्वच्छ ईंधन का उत्पादन, रसायनों से मुक्त जैविक उर्वरक की उपलब्धता और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन का यह त्रिकोणीय संगम 'ग्रीन बनासकांठा' से होते हुए 'ग्रीन गुजरात' के व्यापक संकल्प को हकीकत में बदल रहा है।

## छापेमारी के दौरान बेकाबू भीड़ का हमला: थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मी घायल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

**(जीएनएस)**। सुपौल। बिहार के सुपौल जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां देर रात छापेमारी के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में थानाध्यक्ष मनीष कुमार समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया।

यह घटना राघोपुर प्रखंड के करजाईन थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव की है, जहां पुलिस शराब तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी सरोज कुमार मेहता लंबे समय से फरार था और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। बुधवार देर रात जब पुलिस टीम ने गांव में छापा मारा, तो आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस टीम आरोपी को लेकर वापस लौट रही थी, तभी अचानक हालात बिगड़ गए। आरोपी से जुड़े लोगों और स्थानीय ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया और देखते ही देखते हमला शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले में पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

हमले में थानाध्यक्ष मनीष कुमार को भी चोटें आईं, जबकि अन्य चार पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार, सभी की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त जांच और निगरानी के लिए भेजा गया है।

घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल अतिरिक्त बल को मौके पर भेजा गया। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गांव में फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी है और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया जा रहा है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएसपी बीरपुर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्य आरोपी सरोज कुमार मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस का फोकस हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी पर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटनास्थल से मिले गोली के खोखे का पुलिस फायरिंग से कोई संबंध नहीं है, जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी न फैले।

दूसरी ओर, इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों की भी अलग राय सामने आई है। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना वारंट के गांव में घुसी और कार्रवाई के दौरान मारपीट की, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई थी और आरोपी की गिरफ्तारी पूरी तरह वैध थी।

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे के संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव में रहती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती हैं।

## देश भर में सुविधाजनक पुलियाएँ (सब वे) बनाने का रेल मंत्री का निर्देश

### रेल पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर इन रेल पुलियाओं (सब वे) से लगेगी रोक,पटरी के आर पार इन सुगम पुलियाओं (सब वे) का निर्माण मात्र 12 घंटे में किया जा सकेगा

**(जीएनएस)**। रेल पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को अब रेलवे मिशन मोड में रोकेगा। सुविधाजनक पुलियाएँ (सब वे) बनाकर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी व्यापक तैयारियों के रूप में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों की एक workshop की।

जहाँ रेल पटरी के एक तरफ बस्ती है और दूसरी तरफ़ खेत, विद्यालय, श्मशान या अन्य उपयोगी एवं महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे स्थानों पर ये रेल पुलियाएँ (सब वे) बनाई जायेंगी। रेल मंत्री ने देशभर में ऐसी रेल पुलियाओं (सब वे) को बनाने का निर्देश दिया, जहाँ अपने रोजमर्रा के जीवन में बड़ी संख्या में लोग पटरियों को पार करते हैं।

**जीवनदायी विकल्प के रूप में उभरेगी रेल पुलिया (सब वे)**

- रेल मंत्री ने अधिकारियों को एक ऐसी सुविधाजनक रेल पुलिया (सब वे) बनाने को कहा जो पटरी पार करने वाले लोगों के लिए एक जीवनदायिनी विकल्प के रूप में उभरे।
- इन रेल पुलियाओं (सब वे) को बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि एक आम आदमी साइकिल, मोटर साइकिल तथा कामकाज से जुड़ी अन्य चीजों को भी अपने साथ ले जा सके। इससे देशभर में पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। देश की एक बड़ी आबादी के लिए भारतीय रेल की ये पुलिया (सब वे) वरदान साबित होगी।

**सुगम और सुरक्षित डिज़ाइन**

- रेल मंत्री ने अधिकारियों को देश की इस बड़ी समस्या से अगले 5-6 वर्षों में निजात दिलाने को कहा। ये पुलियाएँ (सब वे) इस प्रकार से बनाई जायेंगी ताकि पटरियों के आर पार इनका निर्माण मात्र 12 घंटे में हो सके।
- रेल मंत्री ने कहा कि, डिज़ाइन इस प्रकार की हो, ताकि लोगों को इसे इस्तेमाल करने में कोई हिचक न हो। जल भराव से पुलिया (सब वे) प्रभावित न हो।
- रेल पुलिया (सब वे) बनाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय पिछले कई दिनों से अधिकारियों के साथ चली आ रही मंत्रणा का परिणाम है।
- रेल मंत्री का मानना है कि, व्यवस्था संवेदनशील हो तथा एक आम आदमी की समस्यों का सभी अधिकारी ऐसा समाधान निकालें जो आने वाले कई दशकों तक प्रभावी रहे।

## पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद एवं मंगलुरु के बीच संचालित की जा रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि को 29 मई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार से यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी तथा अतिरिक्त भीड़ का सुचारु प्रबंधन किया जा सकेगा। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित संरचना, मार्ग, समय एवं रखरखाव व्यवस्था के साथ विशेष किराए पर यथावत संचालित होती रहेगी।

ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) [8 फेरे]

ट्रेन संख्या 09424 प्रत्येक शुक्रवार को अहमदाबाद से 16:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:00 बजे मंगलुरु पहुंचेगी।

**प्रमुख ठहराव:**

यह ट्रेन नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुन्दापुरा, उडुपि, मुल्की एवं सुरतकल स्टेशनों पर ठहरेगी।

**कोच संरचना:**

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे।

**बुकिंग जानकारी:**

ट्रेन संख्या 09424 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों एवं IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यात्रीगण से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें।

## ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार का कड़ा जवाब "देश में पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं"

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर फैल रही कमी की खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि देश में किसी भी प्रकार का ईंधन संकट नहीं है। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने आधिकारिक बयान जारी कर यह साफ किया कि सभी राज्यों में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पेट्रोल पंपों से लेकर गैस एजेंसियों तक पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय स्तर पर यह अफवाह फैलने लगी थी कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है, जिसके चलते लोगों ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त ईंधन भरवाना शुरू कर दिया। इस तरह की अचानक बढ़ी मांग ने कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव जरूर बनाया, लेकिन सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सही मानें, क्योंकि अफवाहें न केवल अनावश्यक घबराहट पैदा करती हैं बल्कि आपूर्ति व्यवस्था पर भी दबाव डालती हैं।

सरकार के अनुसार, देशभर में एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं और कहीं भी राशनिंग लागू नहीं की गई है। न ही किसी पेट्रोल पंप को ईंधन की आपूर्ति सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आम उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन सहज रूप से मिलता रहेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत बताते हुए मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि देश आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवां सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक बन चुका है। भारत 150 से अधिक देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है, जो उसकी उत्पादन क्षमता और वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

वैश्विक स्तर पर भले ही ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हों, लेकिन भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को काफी विविधतापूर्ण बना लिया है। वर्तमान में देश को 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति मिल रही है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव या संकट की स्थिति में भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित नहीं होती।

देश की रिफाइनरियां भी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। ये रिफाइनरियां न केवल घरेलू मांग को पूरा कर रही हैं, बल्कि निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 60 दिनों का पर्याप्त ईंधन स्टॉक मौजूद है, जबकि कुल भंडारण क्षमता 74 दिनों तक की है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक होने का मतलब है कि अचानक मांग बढ़ने या सप्लाई में अस्थायी बाधा आने पर भी आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

एलपीजी आपूर्ति के मोर्चे पर भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक बताई गई है। सरकार के अनुसार, उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है और प्रतिदिन 50 लाख से अधिक गैस सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से मिल रही है।

## उत्तर गुजरात के विकास का नया अध्याय: बेचराजी रणुज रेलखंड तैयार,सीआरएस निरीक्षण प्रस्ताव अग्रेषित

**(जीएनएस)**। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त, 2025 को गुजरात दौरे के दौरान 1,400 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसमें बेचराजी–रणुज रेल खंड भी शामिल था, जिसका ब्रॉडगेज में परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 40 किलोमीटर लंबाई एवं 520 करोड़ की लागत से सम्पन्न इस परियोजना के माध्यम से उत्तर गुजरात को सुदृढ़ रेल संपर्क प्रदान किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की गई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षित, तेज एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।

बेचराजी–रणुज रेल खंड के अंतर्गत मध्यवर्ती प्रमुख स्टेशनों में खांभेल एवं चाणसमा शामिल हैं, जो महेसाणा एवं पाटण जिलों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में परिवर्तन पूर्ण हो चुका है तथा यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने पर इन क्षेत्रों के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी इलाकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों तथा छोटे व्यापारियों के लिए आवागमन अधिक सुगम, तेज एवं किफायती हो जाएगा।

देश के विभिन्न क्षेत्रों से बेचराजी मंदिर एवं वहां आयोजित मेला में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु इस रेल सुविधा से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।

यह परियोजना क्षेत्र के कृषि एवं लघु उद्योगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। किसानों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। साथ ही, यह रेल खंड क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार के अवसरों में वृद्धि में सहायक होगा। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना एवं राज्य की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार लाना है।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि इस खंड पर अब तक मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा था। अब यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने के उद्देश्य से बेचराजी–रणुज रेल खंड का ब्रॉडगेज कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है तथा सीआरएस (Commissioner of Railway Safety) निरीक्षण के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात इस खंड पर यात्री रेल सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध यात्रा सुविधा प्राप्त होगी।

इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में Director G-RIDE श्री राजकुमार, जीएम (सिविल) श्री शिवेन्द्र कुमार, अपर मण्डल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) श्रीमती मंजू मीणा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. जेनिया गुप्ता तथा वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री वैभव सकलेचा उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान महेसाणा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री हरिभाई पटेल के साथ दूरभाष पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उन्हें बेचराजी–रणुज रेल खंड के सीआरएस निरीक्षण हेतु प्रेषित प्रस्ताव, वर्तमान प्रगति एवं आगामी यात्री सेवाओं के संचालन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही, इस रेल खंड के विद्युतीकरण (Electrification) के लिए भी स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई, जिससे भविष्य में इस मार्ग पर और अधिक तेज, पर्यावरण-अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष रेल संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

अहमदाबाद मंडल द्वारा इस परियोजना को उच्च गुणवत्ता मानकों एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया गया है। यह पहल भारतीय रेलवे की यात्री-केंद्रित, आधुनिक एवं विकासोन्मुख कार्यप्रणाली को दर्शाती है। इस रेल खंड के प्रारंभ होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी तथा उत्तर गुजरात के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

## स्वास्थ्य बीमा में रिकॉर्ड उछाल: 1.2 लाख करोड़ पार प्रीमियम, तेज क्लेम निपटान से बढ़ा भरोसा

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। देश का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र तेजी से विस्तार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस सेक्टर ने लगभग 9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए कुल प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है। यह उपलब्धि न केवल बीमा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लोगों की सोच और प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं।

बीते कुछ वर्षों में महामारी के अनुभव, बढ़ते इलाज के खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं की अनिश्चितताओं ने आम लोगों को बीमा की ओर अधिक आकर्षित किया है। पहले जहां स्वास्थ्य बीमा को एक अतिरिक्त खर्च माना जाता था, वहीं अब इसे आवश्यक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

सरकार और नियामक संस्थाओं की सक्रिय भूमिका ने भी इस क्षेत्र को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Insurance Regulatory and Development Authority of India ने बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए तय की गई नई समय-सीमाएं इस दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो रही हैं।

नए नियमों के तहत अब कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन की प्रक्रिया एक घंटे के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि फाइनल ऑथराइजेशन अधिकतम तीन घंटे के अंदर करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद बीमा मंजूरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिससे इलाज में देरी और मानसिक तनाव दोनों बढ़ जाते थे। लेकिन अब इन सख्त समय-सीमाओं के लागू होने से मरीजों को समय पर इलाज मिलना आसान हो गया है और अस्पतालों की कार्यप्रणाली भी अधिक व्यवस्थित हुई है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुई इस वृद्धि के पीछे कई संरचनात्मक कारण भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पॉलिसीधारकों की औसत आयु में वृद्धि, उच्च कवरेज वाली योजनाओं की बढ़ती मांग और चिकित्सा तकनीकों में हो रहे तेजी से विकास ने बीमा लागत को प्रभावित किया है। आधुनिक इलाज, जैसे एडवांस सर्जरी, रोबोटिक ऑपरेशन और विशेष उपचार पद्धतियां महंगी होती जा रही हैं, जिससे बीमा कंपनियों को भी अपने प्रीमियम में समायोजन करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही, क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में आए सुधार ने भी इस क्षेत्र में विश्वास को मजबूत किया है। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में जहां 85.66 प्रतिशत दावों का निपटान हुआ था, वहीं 2023-24 में यह थोड़ा गिरकर 82.46 प्रतिशत रहा। हालांकि, 2024-25 में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह आंकड़ा बढ़कर 87.50 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह सुधार इस बात का संकेत है कि बीमा कंपनियां अब अपने ग्राहकों के दावों को तेजी और पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हैं।

डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग भी इस परिवर्तन का एक अहम कारण है। बीमा कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर दावों की जांच और निपटान को अधिक सटीक और तेज बना रही हैं। इससे फर्जी दावों पर रोक लगाने में भी मदद मिल रही है, जिससे पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ी है।

हालांकि, इस प्रगति के बावजूद चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। Insurance Regulatory and Development Authority of India के 'बीमा भरोसा' पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में सामान्य और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी कुल 1,37,361 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से लगभग 93 प्रतिशत यानी 1,27,755 शिकायतों का निपटारा उसी अवधि में कर दिया गया, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी, यह संख्या यह दर्शाती है कि उपभोक्ताओं को अभी भी कई स्तरों पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इन शिकायतों में प्रमुख रूप से क्लेम में देरी, पॉलिसी की शर्तों को लेकर भ्रम, और अस्पतालों व बीमा कंपनियों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं शामिल हैं। सरकार और नियामक संस्थाएं इन मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके।

स्वास्थ्य बीमा के इस तेजी से बढ़ते दायरे का एक बड़ा सामाजिक प्रभाव भी है। इससे न केवल लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब अधिक लोग बीमा के दायरे में आते हैं, तो वे समय पर इलाज कराने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है और समग्र स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है।

भविष्य की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र और अधिक विस्तार करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेलीमेडिसिन और पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान्स जैसी नई तकनीकों के जुड़ने से यह क्षेत्र और भी उपभोक्ता-केंद्रित बन सकता है। साथ ही, सरकार की ओर से आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विस्तार भी इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कुल मिलाकर, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में आई यह तेज वृद्धि केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक और स्वास्थ्य ढांचे में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है।